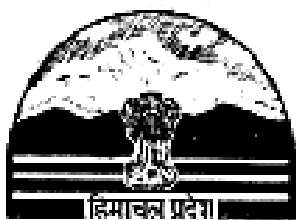


रजिस्टर्ड नं० HP / 13 / SML / 2008.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 9 जून, 2008 / 19 ज्येष्ठ, 1930

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 2008

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)-१२/२००८-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-06-2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में

संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव।

**हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास
निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 06 जून, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति संक्षिप्त नाम। और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

2. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास धारा 5 का निगम अधिनियम, 1979 की धारा 5 की उपधारा (1) में, "चालीस करोड़" शब्दों संशोधन। के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "साठ करोड़" शब्द रखे जाएंगे।

Act No. 11 of 2008.

**THE HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION
(AMENDMENT) ACT, 2008**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 06TH JUNE, 2008)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled
Tribes Development Corporation Act, 1979 (Act No. 20 of 1979).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title. **1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Scheduled
Castes and Scheduled Tribes Development Corporation (Amendment) Act,
2008.

Amendment
of section
5. **2.** In section 5 of the Himachal Pradesh Scheduled Castes and
Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979, in sub-section (1),
for the words “forty crores” wherever these occur, the words “sixty crores”
shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 2008

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-6/2008-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7-06-2008 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2008 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
जे0 एन0 बारोवालिया,
प्रधान सचिव।

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 07 जून, 2008 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 1997 का 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— ²²

“(1) अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे, किन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं।”।

Act No. 12 of 2008.

**THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR
WOMEN (AMENDMENT) ACT, 2008**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 07TH JUNE, 2008)

AN

ACT

*to amend the Himachal Pradesh State Commission for Women Act,
1996 (Act No. 22 of 1997).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh State Short title.
Commission for Women (Amendment) Act, 2008.

2. In section 4 of Himachal Pradesh State Commission for Amendment
Women Act, 1996, for sub-section (1), the following sub-section shall be of section 4.
substituted, namely:—

(22 of
1997)

“(1) The Chairperson and non-official members shall hold office
during the pleasure of State Government but not exceeding three years.”.

